आंसू दिल से आते है, दिमाग से नहीं।
– अज्ञात

जिंदगी बुरी तरह प्रभावित

इंसानी सभ्यता के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया के स्तर पर एक पीढ़ी की शिक्षा में इस तरह का व्यवधान आया। हालांकि स्कूल–क०लेज बंद होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने की कोशिशों के तहत इंटरनेट के जरिए लैपटॉप और स्मार्ट फोन पर अ०नलाइन पढ़ाई की कवायद जारी है।

नीतू सिंह।

कोरोना वायरस ने तमाम मोर्चों पर हमारी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन खासकर शिक्षा व्यवस्था को इसने इस कदर पंगु बना दिया है कि नुकसान का पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस बारे में अभी जो शुरुआती रिपोर्टें और सूचनाएं आ रही हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। पिछले दिनों बच्चों से जुड़े मसलों पर काम करने वाले जाने–माने एनजीओ सेव द चिल्ड्रेन ने एक रिपोर्ट जारी की 'सेव द एजुकेशन'।

इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना से उपजी परिस्थितियों के चलते जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, उनमें लगभग एक करोड़ ऐसे हैं जो दोबारा स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट में यूनेस्को के आंकड़ों का हवाला देकर बताया गया है कि अप्रैल में कोरोना के चलते दुनिया भर के करीब 160 करोड़ बच्चे और किशोर स्कूल–कॉलेजों से बाहर हो गए।

इंसानी सभ्यता के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया के स्तर पर एक पीढ़ी की शिक्षा में इस तरह का व्यवधान आया। हालांकि स्कूल–कॉलेज बंद होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने की कोशिशों के तहत इंटरनेट के जरिए लैपटॉप और स्मार्ट फोन पर ऑनलाइन पढ़ाई की कवायद जारी है, लेकिन इसकी सीमाएं पहले दिन से स्पष्ट हैं। क्लास रूम इंटरैक्शन की जगह फोन पर चलने वाली क्लास ले ही नहीं सकती। मगर बड़ा सवाल तो यह है कि यह सुविधा भी कितने स्टूडेंट्स को हासिल है।

लैपटॉप या स्मार्ट फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ–साथ घर में ऐसा एक अलग कोना भी कितने स्टूडेंट्स को मिल सकता है जहां बैठकर वे फोन के जरिए पढ़ाए जा रहे पाठों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इससे भी बड़ी बात यह कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते आई आर्थिक दिक्कतों ने बहुत सारे परिवारों को जिन हालात में पहुंचा दिया है, उनमें बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाने की वे सोच भी नहीं सकते। इन बच्चों को दाना–पानी जुटाने की कवायद में भी हाथ बंटाना पड़ रहा है और यह काम छुड़ाकर उनकी पढ़ाई का खर्च फिर से सिर पर लिया जाए, ऐसी स्थिति इन परिवारों की जल्दी नहीं होने वाली।

सरकारों के बजट में शिक्षा मद पर किए जाने वाले खर्च में संभावित कटौतियों को रिपोर्ट में एक और चुनौती बताया गया है। अपनी घटती आय को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बजट पर कुल्हाड़ी चलाना सरकारों के लिए सबसे आसान होगा, हालांकि इससे आगे चलकर हालात और खराब होंगे। शिक्षा का हाल कोरोना से पहले भी बहुत अच्छा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक तब भी दुनिया के 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर ही थे। लेकिन यह आपदा उन बच्चों की भी एक बड़ी तादाद को इस व्यवस्था से बाहर धकेल रही है, जो बड़ी मुश्किल से इसमें शामिल हो पाए थे।

इन कठिन परिस्थितियों में बीमारी से राहत मिलते ही अगर शिक्षा को लेकर विशेष प्रयास नहीं किए गए तो 2030 तक दुनिया के सभी बच्चों को स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का वैश्विक लक्ष्य दशकों दूर चला जाएगा।

वास्तविक अर्थ

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

डिक्शनरी के हिसाब से संन्यास का अर्थ है त्याग.... समर्पण। लेकिन समर्पण का अर्थ क्या है?

संत एकनाथ महाराज की बेटी का विवाह एक विद्वान पंडित के साथ हुआ, जो बहुत ही जल्द एक गलत सोहबत का शिकार हुए और देर रात को घर आया करते थे।

जब चिंतित बेटी इस समस्या को लेकर अपने पिता, एकनाथ महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने अपने दामाद को फोन किया और बोलें "तुम एक ज्ञानी मनुष्य हों, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं, इसलिए घर से निकलने से पहले उसे गीता के एक या दो छंद जरूर सुना कर आया करो। उसके बाद उन्हें जहां जाना हो, वहां जाना"। पंडित जी ने एकनाथ महाराज की बात मान ली और नियमित रूप से गीता के छंद अपनी पत्नी को सुनाने लगे।

संपादकीय

महत्वपूर्ण फैसले

मोदी सरकार ने इन कानूनी बदलावों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के संवर्धन और किसानों की समृद्धि के लिए कोरोना काल में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं जिनमें कृषि क्षेत्र में बुनियादी संरचना तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था कॉफी अहम हैं। इस कोष से फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रावधान है। दरअसल, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने में कई फसलें व कृषि उत्पाद 20 फीसदी तक खराब हो जाती हैं। इन फसलों व उत्पादों में फल व सब्जी प्रमुख हैं। इसलिए सरकार ने फॉर्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया है ताकि फसलों की इस बर्बादी को रोककर किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जाए। खेतों के आसपास कोल्ड स्टोरेज, भंडारण जैसी बुनियादी सुविधा विकसित किए जाने से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित होगा और खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र मजबूत होगा। खेतों के पास अगर प्रसस्करण संयंत्र लगने से एक तरफ उनकी लागत कम होगी तो दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की समस्या विकराल बन गई, जिसपर राजनीति तो सबने की लेकिन इस समस्या के समाधान की दृष्टि किसी के पास नहीं थी। दरअसल, गांव से शहर की तरफ या एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ श्रमिकों का पलायन रोजगार की तलाश में ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या का स्थाई समाधान तलाशने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर कोरोना काल में जोर दिया है ताकि गांवों के आसपास वहां के स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले।

किसान अब बिना की रोक–टोक देशभर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसानों को अपनी अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिली और कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार का सपना पूरा हुआ।

किसानों की भी अपनी मर्जी

कैलाश चौधरी।।

कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए संकट का काल है, लेकिन देश में कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों की समृद्धि के लिए यह उषा काल साबित हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने अध्यादेशों के माध्यम से कई ऐसे नीतिगत सुधारों को अमलीजामा पहनाया है जिनका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। किसान अब बिना की रोक–टोक देशभर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसानों को अपनी अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिली और कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार का सपना पूरा हुआ।

महामारी के संकट के दौर में देश की करीब 1.30 अरब आबादी को खाने–पीने चीजों समेत रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कृषि एवं संबद्ध क्षे.त्र की अहमियत सिद्दत से महसूस की गई। यही वजह थी कि कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जब देशव्यापी लॉकडाउन किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को इस दौरान भी छूट देने में देर नहीं की। फसलों की कटाई, बुवाई समेत किसानों के तमाम कार्य निर्बाध चलते रहे। मगर, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में कई राज्यों में एपीएमसी द्वारा संचालित

जींस मंडियां बंद हो गई थीं, जिससे किसानों को थोड़ी कठिनाई जरूर हुई। इस कठिनाई ने सरकार को किसानों के लिए सोचने का एक मौका दिया और इस संबंध में और सरकार ने और अधिक विलंब नहीं करते हुए कोरोना काल की विषम परिस्थिति में किसानों के हक में फैसले लेते हुए कृषि क्षेत्र में नए सुधारों पर मुहर लगा दी।

मोदी सरकार ने कोरोना काल में कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों के समृद्धि के लिए तीन अध्यादेश लाकर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनकी मांग कई दशक से हो रही थी, इन फैसलों से किसान और कारोबारी दोनों को फायदा मिला है क्योंकि नए कानून के लागू होने के बाद एपीएमसी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर किसी भी जींस की खरीद–बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। कृषि बाजार में स्पर्धा बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों को बेहतर व लाभकारी दाम मिलेगा।

केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किया है जिससे खाद्यान्न दलहन, तिलहन व खाद्य तेल समेत आलू और प्याज जैसी सब्जियों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से दिया है। इस फैसले से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ किलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि बरसात के दिनों में उत्पादक मंडियों में फसलों की कीमतें कम होने से किसानों को फसल का भाव नहीं मिल पाता था जबकि शहरों की मंडियों में आवक कम होने से उपभोक्ताओं को उंचे भाव पर खाने–पीने की चीजें मिलती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कारोबारियों को सरकार की ओर से स्टॉक लिमिट जैसी कानूनी बाधाओं का डर नहीं होगा जिससे बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच समन्व बना रहेगा।

इस कानून ने किसानों को बाधामुक्त होकर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी है, जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से उनको औने–पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में यह फैसला सहायक साबित होगा।

अष्टयोग- 5119

	1				2	4
	30	2	37	6	31	
	5		4		1	6
6	30	3	27	1	33	5
	3			5	6	
	33	4	32	4	30	
4	7				2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5118 का हल

4	2	6	3	5	1	7
2	32	4	39	7	34	4
6	1	7	4	3	5	2
5	30	3	38	6	31	1
1	2	5	6	4	7	3
3	27	2	25	1	31	6
7	6	1	4	2	3	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से

मोहन। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इससे जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करने का भी प्रावधान है। वहीं, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है जो कृषि–व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं और आपस में सहमत पारिश्रमिक मूल्य ढांचे पर भविष्य में कृषि उपज की बिक्री के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से और इसके अतिरिक्त एक उचित रूप से संलग्न करने के लिए किसानों की रक्षा करता है और उन्हें अधिकार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में यह कानून काफी अहम साबित होगा क्योकि व्यावसायिक खेते वक्त की जरूरत है। खासतौर से छोटी जोत वाले व सीमांत किसानों के लिए ऐसी फसलों की खेती नामुमकिन है जिसमें ज्यादा लागत की जरूरत होती है और जोखिम ज्यादा होता है।